235.93 करोड़ रुपये (1991 के मूल्य) की अनुमानित लागत की सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना पर नवम्बर, 1993 में परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया और इसे स्वीकार्य पाया गया बशर्ते कि बिहार राज्य सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करें।

(ख) औरंगाबाद जलाशय और सोन नहर आधुनिकीकरण सोपान पर मार्च, 1994 तक प्रत्याशित व्यय क्रमशः लगभग 16.89 करोड़ रु० और 45.22 करोड़ रु० है। योजना आयोग ने आठवीं योजना में औरंगाबाद जलाशय तथा जमानिया और कदवान जलाशय परियोजना सहित सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजन के लिए क्रमशः 20 करोड़ रुपए और 344.90 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपने योजनागत संसाधनों में से किया जाता है।

Allotment of Land to Diplomatic Corps for construction of chancernies and Residencies

*298. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have earmarked some areas in North Delhi for development and allotment/sale to the diplomatic corps for constructions of their chanceries and residences;

(b) the exact location and the total area for this project;

(c) when was the decision taken in this regard and how much delay has since been caused despite reminders from the Ministry of Internal Affairs; and

(d) what are the reasons for delay?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL): (a) and (b) 206 acres of land in Sector 27, Phase-II of the Dwarka Project, located in South West Delhi, has been earmarked for the second Diplomatic Enclave;

(c) and (d) A decision in this regard was taken in October, 1992. In view of the fact that about 40 acres of vacant land is available in the existing Diplomatic Enclave in Chanakyapuri, there is no immediate shortage of land for diplomatic missions. The question of delay, therefore, does not arise.

शुष्क-कृषि में उपज के विकास के लिए अनुसंधान

*290. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री वीरेन्द्र जे० शाह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शुष्क कृषि में उपज के विकास के लिए किया गया अनुसंधान लाभकारी सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस उद्देश्य से पिछले वर्षों में भी एक योजना लागू की थी;

(ग) यदि हां, तो यह योजना किन-किन स्थानों पर लागू की जा रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि विनिर्धारित है;

(घ) इस संबंध में दिसम्बर, 1993 तक कुल कितनी धनराशि पहले ही व्यय की जा चुकी है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उन क्षेत्रों का अनुमानित प्रति हेक्टेयर औसत उपज उत्पादन कितना होगा, जिनमें इसे लागू किया जा रहा है?